you permit me I will take it up. I sought your indulgence....

MR. SPEAKER: You must send the old man to the Minister, instead of bringing it up here.

SHRI SAMAR GUHA: We do not get the opportunity.

MR. SPEAKER: Out of thousands of persons you have brought one individual case.

SHRI SAMAR GUHA: I crave your indulgence.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The Government has decided to set up two freedom-fighters' homeone in Delhi and the other in Pondicherry, for Freedom fighters who are ailing, infirm or physically handicapped, and who have none to look after them.

Till such time as the regular homes are established, a temporary home with limited accommodation for about 25 persons is being set up in Delhi. Well, Sir, I have been in touch with Brahmachari ji and when I conveyed to him the government's decision that we hope to start a temporary home in Delhi from 2-10-74, he was good enough to give up his fast. We have formulated rules for this. I have also written letters to all the Chief Ministers to suggest two names each of such persons who feel who could be accommodated in this home. We are making progress in that direction.

श्री राम चन्द्र विकल मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू जो मामले इनकी जानकारी मे आ चुके है उनके बारे में निर्णय करने में क्या कठिनाई है और रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी ले रहे है वह कब तक प्राप्त हो जायेगी और उस पर कब तक फैसला कर सकेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : केवल उन्ही मामलों का निर्णय नहीं लिया गया है जो संदिग्ध हैं जिनके तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे पास नही हैं और न आवेदनकर्त्ताओं के पास ही हैं। इस सम्बन्ध में जो मैंने तीन मिसालें दीं जिन्होंने दरख्वास्तें दीं वे कहते हैं हमें इस कारण से निकाला गया लेकिन न उनके पास कोई तथ्य है और न हमारे पास अभी कोई पुराने रिकार्ड और फाइलें मिली हैं, तो रक्षा मंत्रालय से हम सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं यद्यपि वहां भी फाइलें नही मिल रही है पुरानी होने के कारण लेकिन उन्होंने कहा है और विश्वास दिलाया है कि जल्दी से ढूंढ कर कागजात भेज देंगे और तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जायेगा।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR: Sir, I would like to know from the hon. Minister what percentages of the citizens have been already sanctioned. I want to know the break-up figures of the number of Army, Navy and Air Force personnel separately.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The total number of applications received upto 31-3-74 is 1,95,042 out of which we have sanctioned 84,724 36,148 have been rejected because of lack of evidence and other things. 20,033 have been filed—either they have been referred to the State Governments for further scrutiny or proofs are not available. In this way the total disposal of applications is 1,40,905 while incomplete pending applications are 62,801.

As regards the break-up of military personnel, I have figuers regarding ex- I.N.A. personnel, 13,917 military personnel have applied out of which 9,611 have been sanctioned; 478 have been rejected,; 2,959 have been filed and thus, the total disposal is 13.048.

SHRI SAMAR GUHA: May we know the figure of I.N.A. civilian personnel?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: We have received 12,237 applications from the I.N.A, civilians out of which we have sanctioned 661, we have rejected 1,332: we have filed 2,645. Thus, the total disposal is 4,638—7,601 incomplete applications are pending.

SHRI PRABODH CHANDRA: May I know from Government if it has come to the notice of the Government that quite a large number of applicants are bogus and many of them who have been granted pensions never took part in any national movement? If so, what action is Government taking against those people who are drawing pensions by giving wrong information?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The complaints alleging irregularities in the grant of pensions to ineligble freedom fighters have been received from time to time. So far, 379 such complaint have been received. All complaints are being enquired into and in 148 cases pensions have been suspended pending enquiry by the State Government. Sixteen cases have been disposed of. Such complaints are examined on merits in consultation with the State Government and suitable orders are issued in each case. We are very careful that no bugur and ineligible persons get pensions

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir m this House the Prime Minister had once announced in reply to a quesetion that freedom fighters from the Royal Indian Navy would be put at par with other freedom fighters for awarding of pensions and Taamarpatras. I would like to know from the hon. Minister in view of the fact that since Royal Indian Navy freedom fighters were not kept in civilian jails and, as such, they are not able to produce necesseary certificates from jail certificates from jail authorities and grant pensions to them?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It was decided that Royal Indian Navy mutiny or uprising....

PROF. MADHU DANDAVATE: It is not 'mutiny'. It is 'uprising'.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Yes, it is uprising. I stand corrected. They have been brought under the ambit of the scheme but so far as the standard of proof is required, the Government has to be satisfied that the sufferings alleged by the persons have really taken place and the sort of proof necessary has been spelt out. If we do not do it the complaint that the hon. Member made regarding bogus pensions would arise.

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन-पत्र स्वतन्त्रता सेनानी दफ्तर से गायब हो जाने के कारण उनके मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है ? यदि हां तो उसका पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा : अगर इस प्रकार की हमें कोई सूचना मिलती है कि कागज हमारे दफ्तर में गायब हो गए हैं तो उसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी की जाती है क्योंकि नियमानुसार जो प्रतिवेदन हमें भेजते है उसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी जाती है इसलिए राज्य सरकार से हम कागज मगवा कर उनको पूरा करके उन पर उचित आदेश देते है।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN. The hon. Minister had assured the House during the course of an Half-an-Hour discussion on the question of pension to freedom fighters that the Government will re-consider the quesetion of granting pensions to the participants in the Moplah rebellion in Kerala. I would like to know from the hon. Minister whether they have taken a final decision on this matter.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: This matter has been brought up from time to time and we have seen all the records and as on today our decision is that it should not be included in the list of freedom fighters.

SHRI K. SURYANARAYANA: I would like to know has the Government appointed its own agency to enquire into these complaints because there are bogus applications which have been recommended by MLAs, ex-MLAs and MPs.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I do not have all the figures but I have given the number of such complaints which have been received and the nature and type of action taken by us. We have a machinery and the State Government is assisting us in making necessary enquiries

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के तापीय विद्युत संयत्रों का कार्यकरण

*245. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्रों और उद्योगों में चलने वाले उन तापीय विद्युत संयत्रों के नाम क्या हैं जो अपनी 80 से 85 प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं तथा वे कब से चल रहे हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन तापीय विद्युत संयत्रों के नाम क्या है जो 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चल रहे है और उनके नाम क्या है जो 60 प्रतिशत से कम क्षमता पर चल रहे है, और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तापीय विद्युत संयत्रों में कुशलता के निरन्तर अभाव के क्या कारण है और उनके कार्यकरण में सुधार करके 1974-75 में कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) दो ताप विद्युत केन्द्र नामत. गुजरात रिफाइनरी (24 मैगावाट) और रेपुसागर विद्युत कम्पनी (125 मैगावाट) ने 1972-73 में 85% के अधिक के संयंत्र क्षमता गुणांक पर कार्य किया है। गुजरात रिफाइनरी विद्युत केन्द्र का प्रतिष्ठापन 1965 से किया गया था जबकि रेपु सागर कम्पनी की 62 5 मैगावाट क्षमता के एक यूनिट का प्रतिष्ठापन 1957 में तथा उसी आकार की दूसरी यूनिट का प्रतिष्ठापन 1968 में किया गया था ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में उन ताप विद्युत केन्द्रों जिन्होंने 1973-74 में 60% क्षमता से कम पर कार्य किया की सूची-सभा पटल पर रख गये विवरण में दी गयी है। ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या (I-8137/74) दो ताप विद्युत केन्द्र नामश महाराष्ट्र में पार्ली (60 मैगावाट) और मध्य प्रदेश में अमर कटक (60 मैगावाट) 80 प्रतिशत से अधिक के संयत्र क्षमता गुणांक पर चल रहे है ।

(ग) कई कारणों से अनेक ताप विद्युत केन्द्र बेहतर कार्य निष्पादन करने में असमर्थ रहे है। ये कारण है – (1) पर्याप्त अनुरक्षण की कमी, कोयले की अनुपयुक्त व अस्थिर किस्म के कारण बार बार होने वाले आउटेजिज (2) प्रणाली भार आवश्यकताए जिनमें उच्च भार गुणांक पर प्रचालन की अनुमति नहीं है (3) लेमी अनुरक्षण और परीक्षण अवधियों का बहुत लम्बी होना। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य में सुधार करने के प्रश्न पर राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के हाल में हुये सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि समुचित किस्म के कोयले इत्यादि को प्रयोग सहित सुधरे अनुरक्षण और प्रचालन द्वारा प्रत्येक ताप विद्युत यूनिट को 1973-74 की अपेक्षा 1974-75 के

दौरान 25 प्रतिशत अतिरिक्त उर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी (ख) में पहली लाइन मे 1972–73 के बजाय 1973–74 होना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी: अध्यक्ष जी देश में बढती हुई बिजली की माग को देख कर और जब स्वय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई निजी और सार्वजनिक थर्मल प्लान्टो मे जो क्षमता गुणाक है वह 80, 85 प्रतिशत से ज्यादा होने हुय भी यह जो विवरण यहा पर रखा हुआ है उसको देख कर दुख होता है । इस में आसाम मे चन्द्रपुर का है 17 प्रतिशत काडला का है 26 प्रतिशत जयपुर का है 2 प्रतिशत यह सम्भवत गलती से छपा है यानी क्षमता गुणाक 2 प्रतिशत है कलकोट का है 15 प्रतिशत नेपानगर का 12 प्रतिशत है तो बढती हुई बिजली की माग को देखकर बिजली की वर्तमान पैदावार मे 60 प्रतिशत तापीय यत्र आने है । ऐसी स्थिति मे यह क्षमता पडी रहना कब मे चालू है और इसको दूर करने का कौन सा प्रयास किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी पहले ता में यह माननीय सदस्य को बताना चाहूगा कि यह जो दो यूनिट्स हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 85 प्रतिशत है 1972–73 मे इसमे एक पब्लिक सैक्टर में है और एक प्राइवेट सैक्टर मे है ।

जहा तक जनरल सवाल है ना अभी जो मीटिंग हुई थी इरीगेशन और पावर मिनिस्टर्स की उसमे और उसके पहले चेयरमैन इलक्ट्रिसिटी बोर्डस की मीटिंग हुई उसमे जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर काफी चर्चा हुई और जिस पर ठोस सुझावो पर चर्चा हुई वह यही प्रश्न था कि इस वक्त जितनी जनरेटिंग कैपेसिटी देश में है उसका अधिकतम उपयोग देश में कैसे किया जाय । और उसम च हे मन्टेनेस की बात हो मसलन आज हमारे देश मे बायलैर की ओवर हाल और मेन्टेनेस के लिये आम तौर से 6 से 8 सप्ताह लगते है, तो हमने सुझाव दिया कि 4 सप्ताह से ज्यादा नही लगने चाहिए और दूसरा मामला है राज्यों ने । चकि अधिकतर यूनिटस राज्यो में हैं तो राज्यो को मनकार के ही हम चला सकते हैं राज्य उनका इतजाम करेंगे । जितनी महायता हम से मागेंगे वह देंगे ।

इसी तरह एक दूसरा प्रश्न आज मेन्टेनेसका है। प्रीवेंटिव मेन्टेनेस की बात साधारणतया कही जाती है और सही है लेकिन उस मे एक कठिनाई यह आती है कि जहा इतनी कमी है बिजली की तो वहा प्रीवेन्टि मेन्टेनेंस के लिये जब रोकना चाहिए प्लान्ट को तब न रोक कर हर राज्य कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली लें । कभी कभी प्रीवेन्टिव मेन्टेनेंस न होने से नुकसान होता है और फिर ब्रैक डाउन हो जाता है। फिर कोयले का प्रश्न है उस की कैसी क्वालिटी हो और कितना कोयला है। इसी तरह से ट्रेनिंग स्पेयर पार्टस का मामला प्लान्ट लोड फैक्टर का मामला है। इस पर बहस हुई और ठोस निर्णय लिये गये । एक-एक मुद्दे पर अलग-अलग बहस हो कर अलग-अलग निर्णय लिये गये ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी जो क्षमता गुणाक के अनुसार काम नही करती है जैसे मत्री जी ने बताया घटिया किस्म का कोयला उस का एक कारण है । तो कम से कम जितने ऐसे तापीय सयन्त्र लगे हुए हैं उन को बढिया किस्म का कोयला उपलब्ध हो क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे ? और आप ने जो निर्णय लिया है कि कम से कम आज की क्षमता का 25 प्रतिशत ज्यादा जैनेरेशन हो क्या उस का प्रबन्ध 1975 के अन्त तक कर सकेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त जहा तक अच्छे कोयले का प्रश्न है, प्रश्न अच्छे या बुरे कोयले

का उतना नहीं है जितना कि जिस कोयले के लिये डिजाइन किया हुआ बायलर है वह है. कोयला मिलना चाहिये। मान लीजिये आप ने बुरे कोयले के लिये डिजाइन किया हुआ है और अच्छा कोयला मिल जाय तो उस से भी नुकसान होगा। तो जिस कोयले के लिये डिजाइन किया गया है उस तरह का कोयला मिलना चाहिए। इस के लिये लिंकेज कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी किस कोयले की खान से किस प्लान्ट में कोयला जायगा इस का निर्णय करती है जब इस वक्त हर पावर प्लान्ट में एक से आठ दिन का कोयला है तो यह दिक्कत आती है कि कोयला उतना अच्छा न भी हो तो भी उस को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्लान्ट चलाना है। फ्यूअल रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहा गया है कि क्वालिटी कंट्रोल का कोई एक प्लान बनाये जो कोयले की खान पर और पावर हाउस पर लागू हो जिस से इस प्रश्न को हल कर सके। यह भी उस मीटिंग में चर्चा हुई।

जहां तक 25 परसेंट बढ़ाना है जैनेरेशन तो वह है इस साल का टारगेट। लेकिन उन यूनिट्स के लिये है जिन की जैनेरेशन 60 परसेंट से नीचे है। जो अच्छे चल रहें है वह तो 25 परसेंट नहीं कर सकते। दूसरों के लिये इसी वर्ष का है।

SHRI K. MALLANNA: The statement shows there is absolutely no thermal plant in Karnataka. In view of the recent failure of the hydro-electric plant in Karnataka, has the Karnataka Government made any request to start a thermal plant in that State?

SHRI K. C. PANT: Karnataka Government has given a scheme on the Kalinadi project, which is again a hydro-electric project. That is a project of importance not only to Karnataka but to the whole of the southern region. At the moment, the starting of a thermal plant in addition to that would involve changing the power plant of the State, which in the present situation of resources does not seem possible.

SHRI KARTIK ORAON: There is about 20 per cent transmission loss of power in our country. In other countries, this loss has been reduced to 5 per cent by suitable devices. That means by taking similar steps in our country also, the loss could be reduced by 15 per cent. At the rate of Rs. 5 crores for 1 per cent of this loss, a sum of Rs. 75 crores could have been saved and utilised for power development. Are Government alive to this loss of power and if so, has any concrete step been taken or likely to be taken to cut down this loss?

SHRI K. C. PANT: Government is very much alive to this loss. The loss is not uniform in all the States; it is more in some Staates and less in others. The problem is, with increased rural electrification taken up rapidly in an effort to reach as many villages as possible in as short a time as possible, various problems have arisen which have increased the line loss. It is possible to reduce this line loss and in fact technological methods to do this have been identified and have been taken up in the recent meeting of the Ministers of Irrigation and Power to which I referred. Some States have put into effect some methods like installation of capacitors, more of substations, changing the size of the conductor, etc. But all this involves investment. While there will be saving, to get to this saving, there has to be an initial investment and the problem is whether to invest on increasing the area of coverage or whether to invest on technological methods to reduce the fine loss. All these are questions which each State has to consider in its own circumstances. The Rural Electrification Corporation has taken up 30 to 40 specific schemes to improve the system so that the line losses can be cut.

श्री भान सिंह भौरा : एक साल पहले इसी हाउस मे यह एलान किया था कि भटिंडा थर्मल प्लान्ट अक्तूबर में चलेगा। उस के बाद दिसम्बर कहा फिर अप्रैल में चलेगा यह कहा गया उस के बाद कहा गया कि जुलाई मे चलेगा। तो वह कब चलेगा यह में जानना चाहता हूं ताकि पंजाब को बिजली मिल सके।

MR. SPEAKER: it is not relevant. The question is about existing plants

अभी परसों पूछा है।

श्री भान सिंह भौरा: वह फटिलाइज के बारे मे था।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह सच है कि कोयला चालित बिजली के कारखानो मे उत्पादन मे कमी का एक बहुत बडा कारण यह भी है कि समय पर इन कारखानो को कोयला पहुचाने की व्यवस्था नही की जाती है और उनके यहा पर्याप्त स्टाक कोयले का नही रहता है? क्या इस वजह से भी बिजली के उत्पादन मे बाधा उत्पन्न नही होती है? अगर इस तरह की शिकायतें आपको मिलती रही है तो इसे दूर करने के लिये आपने कौन-सी व्यवस्था की है ताकि कोयले के स्टाक की कमी वहा है होने पाए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोयले का स्टाक जितना इस वक्त पावर हाउसेस मे है उससे ज्यादा होना चाहिये इस बात को में मानता हू चाहे रेल मत्रालय हो और चाहे माइज मत्रालय दोनो ही प्रयास करते है कि पावर प्रोडक्शन में कमी न आने पाए कोयले की कमी की वजह से। कोयला वहा पहुचा है लेकिन यह जरूर है कि स्टाक कम है। लेकिन पावर प्लाटस को उन्होंने रुकने नही दिया है। दोनो मत्रालयों ने मिल कर इस काम को किया है। यहा एक कट्रोल रुम भी बनाया है। ये और हम तीनों मिल कर इस काम को करते है ताकि कोई पावर प्लान्ट रुकने न पाये। माननीय सदस्य को जान कर खुशी होगी कि जब रेलवे में स्ट्राइक हुई उस वक्त कोयले का स्टाक वहा कुछ बढ़ गया था।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना और बरौनी में बराबर कमी रहता है।

श्री पन्नालाल बारूपाल : अभी इन्होने कहा कि गावो का विजलीकरण हो रहे है। यमुनानगर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहा गावों के बहुत से किसान ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं लेकिन उनको बिजली नही मिलती है और न ही गावो के लिये विद्युतीकरण की राजस्थान सरकार के पास कोई योजना है क्या आप राजस्थान सरकार पर और देगे कि उस कृषि प्रधान क्षेत्र को वह बिजली देने की कोशिश करे ताकि अधिक अन्न उपजाने मे वहा मदद मिल सके—

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न तो थर्मलपावर प्लाटस के बारे मे है।

श्री पन्नालाल बारूपाल जो मेरे दिमाग मे आया पूछ लिया।

अध्यक्ष महोदय : आपके दिमाग मे तो आया लेकिन मेरे मे नही आ रहा है।

SHRI VIKRAM MAHAJAN: Mere fixation of targets is not enough. It has to be backed up by two things, namely, incentive and penalty for non-fulfilment You have fixed certain targets. But the people in charge have no incentives to improve the thermal plant and they have no fear of any penalties Could you not ensure that those persons in charge of thermal plants have to pay for not achieving the targets?

SHRI K. C. PANT: The incentive scheme has been introduced by UP. This is one of the subjects that was considered at the recent Irrigation and Power Ministers' Conference. Because the question of incentives is a complicated one, it was decided to refer it

to a Committee of experts to go into this matter. That is where the matter rests. I can see that the generation is different in different plants. But there are other facts also responsible for this, some of which I have mentioned earlier.

SHRI P. K. DEO: It is an accepted fact that thermal power is costlier than hydel power. So, Government should decide to tap the hydel power potentialities rather than setting up more thermal plants. So far as Orissa is concerned, there is one thermal plant at Talcher, which is working only 24 per cent of its capacity, and the cost of power generation is 25 paise per unit. Instead of providing Rs. 40 crores for the expansion of the Talcher thermal plant, will the Government consider tapping the various hydro-electric projects in Orissa State, like the Indravathi project, where the cost of generation is the lowest in the country and which is capable of generating 600 megawatts of power in the next Plan?

SHRI K. C. PANT: My hon. friend has discussed this matter with me outside the House also. There is no question of thermal versus hydro in this matter. There are some advantages in having hydro stations, but there are also some advantages in having thermal stations, particularly in areas where coal deposit can be easily located. The advantage above all is that we can have a proper mix of thermal and hydro to take care of the peak capacity and run the thermal unit as the base load station.

So far as the particular project which has been referred to by my hon. friend and about which he is very keen and is concerned, there is a procedure to examine these projects and approve them. I cannot talk about individual projects here

Utilisation of Power for Industrial and Agricultural Purposes

*246. SHRI K. MALLANNA:
SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps to minimise the non-essential use of power with a view to its utilisation for industrial and agricultural purposes; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI K. C. PANT): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Distribution of power to the consumers and stipulation of relative priorities therefor is a matter with in the purview of the State Governments. Steps to limit or minimise the use of power for non-essential purposes such as illuminations etc., to conserve the available power for priority uses such as essential services, defence needs, industrial and agricultural proposals were discussed in the Conference of Chairmen of State Electricity Boards and of State Ministers of Irrigation and Power in July, 1974. The Government of India had earlier last year carried out detailed studies State-by-State of power requirements and availability and given guidelines to each State for rational utilisation of the available power to meet the priority needs as fully as possible. These guidelines were further reviewed and revised this year and a special category of priority introduced for industries serving as inputs to the power and energy sector itself. Another category identifying the non-essential consumers has also been incorporated in the guidelines so that power consumption for such non-essential purposes could be curbed.